गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 272
दि. 03.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

डील पक्की! ट्रेड गेम में अमेरिका झुका, भारत की हुई जीत, इण्डिया पर टैरिफ घटाकर 18% किया

यह घोषणा ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिन में पहले हुई एक टेलीफोन बातचीत के बाद की गई।

(जीएनएस)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले अपने पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमत हो गया है। इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास के तौर पर देखा जा रहा है।

यह घोषणा ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिन में पहले हुई एक टेलीफोन बातचीत के बाद की गई। अमेरिकी नेता ने इस बातचीत को "गरिमापूर्ण" और मैत्रीपूर्ण बताया था।

पिछले साल, वाशिंगटन ने अपने लिबरेशन डे शुल्क के तहत भारतीय वस्तुओं पर 25% आयात कर लगाया था। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल के आयात पर एक और 25% शुल्क भी लगाया गया था, जिससे भारत सबसे अधिक शुल्क वाले देशों में से एक बन गया था।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में बताया कि उन्होंने मोदी के साथ "व्यापार सहित कई बातों और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने" पर चर्चा की थी। उनके अनुसार, इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मोदी रूसी तेल की खरीद रोकने और इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से ऊर्जा आयात बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने सुझाव दिया कि यह बदलाव यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में मदद कर सकता है।

यह घोषणा ऐसे समय में भारत-अमेरिका व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दशार्ती है जब तीव्र शुल्क तनाव मौजूद हैं। पिछले साल, अमेरिका ने नई दिल्ली के रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को लक्षित करते हुए भारतीय वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क सहित कठोर शुल्क लगाए थे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विस्तृत और व्यक्तिगत बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनका पूरा बयान यहाँ दिया गया है:

68000 सरकारी कर्मचारियों पर चला योगी का हंटर, एक गलती पर रोक दी तन्ख्वाह, वजह रही निदेर्शों का पालन न करना

(जीएनएस)।

लखनऊ में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। ये वे कर्मचारी हैं जिन्होंने 31 जनवरी की तय समय-सीमा तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा 'मानव संपदा पोर्टल' पर अपलोड नहीं किया। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई साफ निदेर्शों का पालन न करने की वजह से की गई है।

क्यों रोकी गई तन्ख्वाह

उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें। जिन कर्मचारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, उनका वेतन अगली सूचना जारी होने तक रोक दिया गया है।

किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी पर गिरी गाजे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, समय-सीमा तक संपत्ति का विवरण जमा न करने वालों में 34,926 समूह 'ग' के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा 22,624 समूह 'घ' स्टाफ, 7,204 समूह 'ख' अधिकारी और 2,628 समूह 'क' के अधिकारी भी इस सूची में हैं। यानी यह लापरवाही हर स्तर के कर्मचारियों में देखने को मिली है।

वेतन रोकना आखिरी कदम नहीं, आगे और कार्रवाई संभव

अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वेतन रोकने की कार्रवाई अंतिम नहीं है। अगर कर्मचारी जल्द से जल्द अपनी लंबित संपत्ति घोषणाएं जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आगे और सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का साफ संदेश है कि नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहले दी गई थी चेतावनी

सैलरी रोकने से पहले बाकायदा योगी सरकार ने चेतावनी दी थी। जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें। ऐसा न करने पर सैलरी रोक दी जाएगी। इसका पहल का मकसद था उन कर्मचारियों की पहचान करना जिन्होंने रिश्वत या दूसरी काली कमाई से अपनी संपत्तियां खड़ी कर ली हैं।

सामने आ गया रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा का रिसेप्शन वेन्यू, गेस्ट लिस्ट भी हुई तैयार

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जोड़ी 26 फरवरी 2026

को उदयपुर के एक भव्य महल में सात फेरे लेगी। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद अब उनकी शादी की तैयारियां पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें दोनों परिवार सक्रिय रूप से शामिल हैं।

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार, विजय और रश्मिका एक इंटीमेट वेडिंग की योजना बना रहे हैं।

खुशखबरी, 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' के तहत महिलाओं को जल्द मिलेगा 2100 रुपये, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' के तहत मिलने वाली मासिक सम्मान निधि में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति संभाजीनगर में इस संबंध में एक बड़ी घोषणा की है, जिससे लाभार्थियों में उम्मीद जग गई है।

विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना से तत्कालीन महायुति सरकार को भारी लाभ मिला था। सत्ता में लौटने के बाद, महायुति गठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान 'लाडकी बहनों' की मासिक सम्मान निधि ₹1500 से बढ़ाकर ₹2100 करने का वादा किया था। हालांकि, सरकार के डेढ़ साल पूरे होने के बावजूद यह वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने पहले भी कई बार इस सम्मान निधि को ₹1500 से ₹2100 करने का संकेत दिया था। अब छत्रपति संभाजीनगर में उन्होंने फिर से इसकी घोषणा की है, जिससे योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले पैसों में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना मजबूत हुई है।

शिंदे बोले- मैं दिया गया वचन निभाने वाला व्यक्ति हूं

शिंदे ने आगे कहा, "मैं दिया गया वचन निभाने वाला व्यक्ति हूं। यह महाराष्ट्र के मन की सरकार है और हम लाडकी बहनों को लखपति बनाएंगे।" उन्होंने ₹2100 देने के वादे को दोहराते हुए कहा, "हमने जो शब्द दिया था, उसे पूरा करेंगे।" शिंदे ने इसी दौरान किसान कर्जमाफी का निर्णय भी उचित समय पर लेने की बात कही।

डिप्टी सीएम शिंदे बोले- धन-संपत्ति से बढ़कर लोगों का प्रेम है

घोषणा में, एकनाथ शिंदे ने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' की निरंतरता को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा, "यह योजना कभी बंद नहीं होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता।" उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के कथन का जिक्र किया कि "सत्ता आती-जाती है, लेकिन एक बार नाम चला जाए तो वापस नहीं आता।" शिंदे ने यह भी कहा कि उनके लिए धन-संपत्ति से बढ़कर लोगों का प्रेम है।

महाराष्ट्र के जिला परिषद चुनाव से पहले महायुति का बड़ा दांव

डिप्टी सीएम की ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब राज्य में जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

फिल्म इंडस्ट्री से 2025 में सरकार को हुआ करोड़ों का फायदा, बजट से प्रोड्यूसर्स कर रहे कौन सी मांग

साल 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहा अच्छा, करीब 1800 (छोटी-बड़ी) फिल्में बनीं और कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 13,395 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। ज्यादा टिकट बिक्री से सरकार को हुआ फायदा आपको बता दें कि मूवी टिकट पर लागू 18 फीसदी GST के आधार पर सरकार को सिर्फ टिकट बिक्री से करीब 2411 करोड़ रुपये का टैक्स मिला है। न सिर्फ मेकर्स के लिए मुनाफा कमाया बल्कि सरकार के खजाने में भी बड़ी हिस्सेदारी डाली है। सरकार के लिए सैकड़ों करोड़ का राजस्व तैयार करते हैं। नती हैं, जो हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी, बांग्ला, असमिया,उड़िया सहित 24 भाषाओं में रिलीज होती हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 10 से 12 फिल्में ही ब्लॉकबस्टर बन पाती हैं बाकी औसत या घाटे में रह जाती हैं।

प्रोड्यूसर्स की बड़ी मांगः GST कम हो और टिकट दर नियंत्रित हो

फिल्म निमार्ताओं की लंबे समय से मांग रही है कि 100 रुपये से ऊपर की टिकट पर लगने वाला 18 फीसदी GST कम किया जाए, मल्टीप्लेक्स में बढ़ती टिकट कीमतों पर नियंत्रण हो और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना है कि महंगी टिकटें दर्शकों को सिनेमाघरों से दूर कर रही हैं।

सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के पुनर्जीवन की जरूरत

निमार्ताओं का सुझाव है कि सरकार शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटरों को प्रोत्साहित करें ताकि कम बजट और कंटेंट आधारित फिल्मों को भी दर्शक मिल सकें।

टैक्स फ्री और राज्य सरकारों की फिल्म नीति

-कई राज्य सरकारें अपनी फिल्म नीति के तहत फिल्मों को सब्सिडी और सुविधाएं देती हैं। उत्तर प्रदेश की फिल्म 'बंधु नीति' इसका उदाहरण है। समय-समय पर कुछ फिल्मों को टैक्स फ्री भी किया जाता है, जिससे दर्शकों की संख्या बढ़ती है।

संक्षिप्त समाचार

'कांग्रेस के शासनकाल में, अक्साई चिन', रिजिजू ने चीन सीमा गतिरोध विवाद पर राहुल गांधी को लेकर लगाया आरोप

लोकसभा के बजट सत्र में 2 फरवरी 2026 को जमकर हंगामा हुआ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक

अप्रकाशित पुस्तक का जिक्र किया और जैसे ही उन्होंने सदन में पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब से एक बयान पढ़ा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उन्हें रोकने के लिए खड़े हो गए।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन सीमा गतिरोध के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोला है।

कुदरत का निजाम भी नहीं बचा पाएगा! सिर्फ इस एक गलती से पाकिस्तान होगा पूरे वर्ल्ड कप से बाहर

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर विवादों और मुश्किलों के भंवर में फंस गई है। भारत के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबले का बहिष्कार करने के फैसले ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट के लीग चरण में ही बाहर होने की कगार पर खड़ा कर दिया है।

बिना मैदान पर उतरे ही पाकिस्तान ने 2 अंक गंवा दिए हैं, जो अब आधिकारिक तौर पर भारत के खाते में चले गए हैं। आईसीसी नियमों के अनुसार, यदि कोई टीम मैच खेलने से इनकार करती है, तो विपक्षी टीम को विजेता घोषित कर 2 अंक दे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ग्रुप-अ का समीकरण पूरी तरह बदल गया है।

भारत को बिना खेले ही 2 अंक मिलने से नेट रन रेट भी मजबूत हो गया है। पाकिस्तान के पास एक मैच गंवाने के बाद 0 अंक हैं और अब उनके पास वापसी के लिए केवल 3 मैच बचे हैं। इससे उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो चली है।

वरुअ और नीदरलैंड्स बन सकते हैं 'विलेन'

पाकिस्तान के लिए असली खतरा अब भारत नहीं, बल्कि वरुअ और नीदरलैंड्स जैसी टीमें हैं। अगर लीग चरण में इनमें से कोई भी टीम पाकिस्तान को उलटफेर का शिकार बना लेती है, तो पाकिस्तान का सफर सुपर-8 से पहले ही खत्म हो जाएगा।

'शायद उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है', राहुल गांधी के चीन सीमा गतिरोध पर दिए बयान पर कंगना रनौत ने किया पलटवार

(जीएनएस)।

लोकसभा में सोमवार को डोकलाम गतिरोध पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के संस्मरण "फोर स्टार्स टू डेस्टिनी" को लेकर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन सीमा मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इस चर्चा की शुरूआत की। जवाब में, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावों का कड़ा खंडन किया और जोर देकर कहा कि मौजूदा शासन में भारत की एक इंच भी जमीन नहीं खोई गई है।

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्षी नेता पर तीखा हमला बोला है। रनौत ने आरोप लगाया कि संसद के भीतर सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और अव्यवस्था फैलाई जा रही है।

शायद उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध

है...

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हवाले से कहा, "वे एक ऐसी किताब में लिखी बातों का जिक्र कर रहे हैं जो प्रकाशित भी नहीं हुई है, क्योंकि शायद उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है... यह कितना बड़ा अपराध है। उन्हें संसद या सांसदों की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्होंने एक घंटे तक यह हंगामा किया।"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किस किताब का किया जिक्र?

नियम 193 के तहत हुई एक चर्चा के दौरान, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब के अंशों का हवाला दिया।

हेग आर्बिट्रेशन को भारत ने किया खारिज, पाकिस्तान से तनाव के बीच सिंधु जल संधि पर कायम

(जीएनएस)।

हेग स्थित मध्यस्थता अदालत द्वारा सिंधु जल संधि के तहत नई सुनवाई शुरू किए जाने और भारत से दस्तावेजों की मांग के बीच, नई दिल्ली ने इस पूरी प्रक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि यह न्यायाधिकरण अवैध रूप से गठित है और वह इसके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

सरकारी सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी ने बताया है कि भारत हेग की इस मध्यस्थता अदालत को "तथाकथित और अवैध रूप से गठित" मानता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत न तो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेगा और न ही अदालत से आए किसी भी संचार या आदेश पर प्रतिक्रिया देगा।

पोंडेज लॉगबुक साझा करने के आदेश पर विवाद

ताजा विवाद अदालत के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें भारत से उसके जलविद्युत परियोजनाओं-बगलिहार और किशनगंगा-से संबंधित "पोंडेज लॉगबुक" साझा करने को कहा गया है। यह आदेश अदालत के "सेकंड फेज ऑन द मेरिट्स" के तहत पारित किया गया है। अदालत का कहना है कि भारत ने अब तक कोई प्रति-ज्ञापन दाखिल नहीं किया है और न ही कार्यवाही में शामिल होने की मंशा दिखाई है।

संधि निलंबित, इसलिए जवाब की जरूरत नहीं

भारतीय अधिकारियों का मानना है कि पूरी कार्यवाही निरर्थक है क्योंकि सिंधु जल संधि को फिलहाल निलंबित रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, भारत का रुख है कि जब वह अदालत के अधिकार क्षेत्र को ही स्वीकार नहीं करता, तो उसके आदेशों का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

पाकिस्तान की कूटनीतिक और कानूनी सक्रियता

भारत के संधि निलंबन के बाद पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक और कानूनी प्रयास तेज कर दिए हैं। इस्लामाबाद ने दूतों को सक्रिय किया, संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है। पाकिस्तान की कृषि बड़े पैमाने पर सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है और सीमित जल भंडारण क्षमता के चलते यह मुद्दा उसके लिए रणनीतिक दबाव बिंदु बन गया है।

हमले के बाद बदला भारत का रुख

यह गतिरोध 23 अप्रैल, 2025 को शुरू हुआ, जब पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया और जल-साझाकरण को राज्य-प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि शत्रुता के माहौल में सहयोग संभव नहीं है।

सम्पादकीय

आर्थिक सुधार को सही दिशा में बनाये रखने का बजट

सुधार का संकल्प, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना नौवां बजट प्रास्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार के उद्देश्य से 'लोगों का' बजट पेश किया है किन्तु स्पष्ट रूप से यह लोकप्रियता या लोकलुभावन बजट बिल्वुल नहीं है। दरअसल इस बजट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आतंक की छाया तो है ही साथ ही अभी तक यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन एवं दूसरे देशों के साथ हुए और होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर आर्थिक पटरी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। देश में विदेशी प्रात्यक्ष निवेश में कमी आने के कारण भी सरकार को बजट में लीक से हटकर प्रावधान करने की जरूरत पड़ी। इसलिए सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने, सहभागिता बढ़ाने, व्रय की क्षमता बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र में लचीलापन लाने की जो कोशिश की है उसे वित्त मंत्री से 'विकास एक्सप्रोस' कहलवाया है। सरकार ने 2025 के वित्त वर्ष के दौरान ही जीएसटी में भारी कटौती करके उपभोक्ताओं को राहत दिया था ताकि ट्रंप टैरिफ के कारण बाजार को मंदी से न जूझना पड़े। यही कारण है कि अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पाद के महंगा होने के बावजूद भारत में उत्पादकता बहुत ज्यादा प्राभावित नहीं हुआ। बजट में टेक्सटाइल इकोसिस्टम को विकसित एवं मजबूत करने के लिए ही सरकार ने बुनकरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी हैण्डलूम योजना में पूंजीगत सहायता योजना का एलान करके न सिर्प टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा दिया बल्कि छोटे स्तर पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। एमएसएमई के बिना इतनी विशाल जनसंख्या को रोजगार दे पाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करके कि विकास का वाहन वुटीर उद्योग ही बन सकता है, बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने की पहल भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि वह बजट के माध्यम से आर्थिक ग्रोथ, सबकी उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ व सबका विकास करे इसलिए सरकार ने तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू, चंदन की लकड़ी के पेड़ों को बढ़ाने के लिए उसकी खेती के प्रोत्साहन पर बल दिया है। इस खेती से वृषि क्षेत्र में जबरदस्त आर्थिक विकास दर में उछाल की उम्मीद है। सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में वैंसर एवं शुगर जैसी सात गंभीर बीमारी की दवाओं को सस्ता तथा टेस्टिंग सुविधा में विस्तार करके अपने सामाजिक दायित्वों का एहसास कराया है। एक जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था में बुजुर्गो, कमजोर आर्थिक वर्ग, महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार को इस तरह के प्रावधान करने ही होते हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा प्रावधान जैसा तो वुछ नहीं किया है किन्तु निजी विश्वविद्यालयों के खोलने में मदद करने की बात जरूर कही है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 पर्यटन स्थलों को चुना है जिसमें 10 हजार गाइड प्राशिक्षित किए जाएंगे। लेकिन बौद्ध सर्विट के माध्यम से मणिपुर से मिजोरम तक जो बौद्ध तीर्थ स्थलों को विकसित करने का प्रास्ताव किया है उससे भारत में चीन, जापान, कोरिया एवं आसियान देशों के पर्यटकों का भारत आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस विदेशी मुद्रा की आवक भी बढ़ेगी। सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब को तो नहीं बढ़ाया किन्तु करदाताओं को राहत देते हुए इतना जरूर किया कि आर्थिक दंड भुगतान करके जेल जाने से छूट हासिल कर सकते हैं। सरकार ने बजट भाषण के दौरान इस बात का एलान किया कि 1 अप्रौल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया जाएगा। इसी तरह बजट में प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्ति की घोषणा करके आपराधिक कार्रवाई से बच सकते हैं बशर्ते उन्हें 30 प्रातिशत का भुगतान करना होगा। सरकार ने वित्तीय घाटे के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में जो 4.5 प्रातिशत का वादा किया था उसे पूरे वित्तीय वर्ष में वित्तीय अनुशासन के माध्यम से पूरा कर लिया और वर्ष 2026-2027 के बजट में 4.3 प्रातिशत वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य निर्धारित किया है।

डोकलाम के 73 दिन, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, डटी रही भारतीय सेना, बिना गोली चलाए रोक दिए थे चीनी सैनिक

(जीएनएस)।

लोकसभा में सोमवार को डोकलाम विवाद ने अचानक सियासी तापमान बढ़ा दिया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तीखे पलटवार के बाद सदन करीब 45 मिनट तक हंगामे की गिरफ्त में रहा। इस बहस ने देश को एक बार फिर 2017 के उस ऐतिहासिक डोकलाम गतिरोध की याद दिला दी, जिसने भारत-चीन संबंधों को नई दिशा दी थी।

क्या है डोकलाम और क्यों है इतना संवेदनशील?

डोकलाम पूर्वोत्तर भारत में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक रणनीतिक पठार है। यह भारत, भूटान और चीन (तिब्बत) का ट्राई-जंक्शन क्षेत्र है। भूटान इसे अपना इलाका मानता है, जबकि चीन इस पर 'डोंगलांग' के नाम से दावा करता रहा है। भारत के लिए डोकलाम इसलिए अहम है क्योंकि यहां चीनी मौजूदगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर-यानी 'चिकन नेक'-के बेहद करीब पहुंच सकती है, जो पूर्वोत्तर भारत की जीवनरेखा है।

सड़क से शुरू हुआ विवाद, आमने-सामने आई सेनाएं

जून 2017 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने डोकलाम में सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। 16 जून को काम तेज हुआ, जिस पर भूटान ने विरोध जताया, लेकिन चीन ने आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 18 जून को भारत ने हस्तक्षेप किया। सिक्किम के रास्ते करीब 270-300 भारतीय सैनिक डोकलाम पहुंचे और

चीनी निर्माण कार्य को रोक दिया।

73 दिन का सैन्य गतिरोधः एक भी गोली नहीं, लेकिन जबरदस्त तनाव

डोकलाम में दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने खड़े हो गए। आगे कुछ सौ जवान थे, लेकिन पीछे हजारों सैनिक अलर्ट पर थे। चीन लगातार आक्रामक बयान दे रहा था और भारतीय सेना पर 'अतिक्रमण' का आरोप लगा रहा था। इसके बावजूद भारत ने भूटान की संप्रभुता और अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए 73 दिनों तक मोर्चा संभाले रखा।

कूटनीति की जीतः कैसे खत्म हुआ गतिरोध?

16 जून से 28 अगस्त 2017 तक चला यह टकराव अंततः 'एक्सपीडिशस डिसएंगेजमेंट' पर खत्म हुआ। दोनों पक्ष पीछे हटे, चीन ने निर्माण उपकरण हटाए और सड़क निर्माण रोक दिया। भारत ने अपने सैनिक वापस बुलाए। यह समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात प्रस्तावित थी।

अजित डोभाल की बीजिंग यात्रा और बैक-चैनल डिप्लोमेसी

इस संकट के समाधान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की भूमिका अहम रही। जुलाई 2017 में बीजिंग जाकर उन्होंने चीनी नेतृत्व से बातचीत की। ब्रिक्स एनएसए बैठक के दौरान शी जिनपिंग के सलाहकार यांग जीची से हुई चर्चा को गतिरोध तोड़ने में निर्णायक माना जाता है।

संसद में सियासत क्यों गरमाई?

सोमवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि डोकलाम की 'हकीकत' सेना जानती है, लेकिन सरकार जनता से छिपा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि अप्रकाशित किताब के आधार पर संसद में बयान कैसे दिया जा सकता है। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

क्यों आज भी प्रासंगिक है डोकलाम?

डोकलाम सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, भूटान की संप्रभुता और चीन के विस्तारवादी रवैये से जुड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि आठ साल बाद भी यह मामला संसद से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक बहस का केंद्र बना हुआ है।

महरौली : सीएम रेखा गुप्ता ने दिया 135 करोड़ का फंड, विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी होगा पेश

(जीएनएस)।

दिल्ली की ऐतिहासिक विधानसभा महरौली अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कालूराम चौक पर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 135 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

इस मौके पर उन्होंने साफ कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला विकास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के हर इलाके को बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

135 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, विधायक का भी पेश होगा रिपोर्ट कार्ड

इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि महरौली विधानसभा और क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र यादव का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि अब विकास कार्यों की जवाबदेही तय होगी और जनता को यह जानने का अधिकार होगा कि उनके इलाके में क्या काम हुआ और क्या बाकी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दक्षिणी दिल्ली की बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा में 304 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की शुरूआत कर चुकी हैं। महरौली के 135 करोड़ जोड़ने के बाद दक्षिणी दिल्ली की चार विधानसभाओं में कुल विकास राशि 439 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

सड़क, पार्क, शौचालय से लेकर सामुदायिक भवन तक

मुख्यमंत्री ने बताया कि महरौली में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं। इसमें सड़कों की मरम्मत और दोबारा निर्माण, पुराने चौपालों और सामुदायिक भवनों का जीर्णोद्धार, नए सार्वजनिक शौचालय, पार्कों का सौंदर्यीकरण, बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए ओपन जिम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन कामों से

इलाके की तस्वीर बदलेगी और नागरिक सुविधाएं मजबूत होंगी।

महरौली के लिए कुल 235 करोड़ का फंड मंजूर

रेखा गुप्ता ने कहा कि महरौली सिर्फ एक विधानसभा नहीं बल्कि दिल्ली के इतिहास और संस्कृति की पहचान है। मां योगमाया मंदिर, लौह स्तंभ, आर्कियोलॉजिकल पार्क और प्राचीन इमारतों से घिरी यह जगह हजारों साल पुराने विरसे की गवाह है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महरौली के लिए कुल 235 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। इस राशि से पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई विभाग और डुसिब मिलकर विकास कार्यों को अंजाम देंगे।

अस्पताल, पार्किंग और एलिवेटेड रोड पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बदरपुर-महरौली एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक की समस्या कम होगी। इसके अलावा 100 से 200 बेड का आधुनिक अस्पताल, मल्टी लेवल पार्किंग, खेल का मैदान और नए सामुदायिक भवन बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन प्रोजेक्ट्स से महरौली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, यातायात और सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी और इलाका तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

भारत से मैच का बॉयकॉट करने के बाद ई-मेल की नौटंकी, पाकिस्तान ने शुरू किया नया ड्रामा

(जीएनएस)।

क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही रोमांच और विवादों से घिरा रहता है। 2026 के ळ20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हैं। ताजा मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ढउइ) के ईमेल ड्रामे का है।

हाल ही में खबरें आई थीं कि पाकिस्तान ने 2026 ळ20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है और वह इस मुकाबले का बहिष्कार कर चुका है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि पाकिस्तान अब कउउ को कोई औपचारिक ईमेल नहीं भेजेगा। कल तक जो पाकिस्तान कड़े रुख की बात

कर रहा था, अब उसके सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं।

पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है?

दरअसल पाकिस्तान सरकार ने मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की थी लेकिन अब आईसीसी को ईमेल नहीं भेजने का नाटक भी कुछ सोचकर ही किया जा रहा है। अगर आधिकारिक रूप से मेल भेजा जाएगा, तो आईसीसी कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। इस वजह से पाकिस्तान ने बीच का रास्ता निकालने वाला पैंतरा अपनाया है।

वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूनार्मेंट में भारत-पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा कमाई कराता है। अगर पाकिस्तान पीछे हटता है, तो कउउ को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल स्थिति 'वेट एंड वॉच' (इंतजार करो और देखो) वाली है। पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक चिट्ठी न जाना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। पाकिस्तानी टीम के मैचों को पहले से ही श्रीलंका में आयोजित कराने पर सहमति बन गई थी। देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।

वर्ल्ड कप फैंस की मौज! टीवी और मोबाइल पर यहां दिखेंगे टी20 वर्ल्ड कप मैच, आईसीसी का बड़ा ऐलान

(जीएनएस)।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साल 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (ळ20 हङ्म१'ि उ४स्र 2026) को लेकर आईसीसी (कउउ) ने आधिकारिक तौर पर ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स का ऐलान कर दिया है। अब यह साफ हो गया है कि भारतीय फैंस वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ अपने टीवी और मोबाइल पर कहां और कैसे उठा सकेंगे।

आईसीसी ने वार्म-अप मैचों का सीधा प्रसारण करने वाले चैनलों की घोषणा की है, उन चैनलों पर ही मुख्य मैचों का प्रसारण किया जाएगा। टीवी के अलावा मोबाइल के ऊपर भी मैचों का लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा।

आईसीसी की ताजा घोषणा के अनुसार, भारत में टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

यानी आप अपने घरों में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर मैच देख सकेंगे।

वहीं, अगर आप सफर में हैं या मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए जियो-हॉटस्टार का प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा। जियो और हॉटस्टार के मर्जर के बाद यह पहला बड़ा आईसीसी टूनार्मेंट होगा, जिसे इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा।

कब लिया गया प्रसारण का फैसला

बीसीसीआई के मैचों की तरह आईसीसी के मैचों के लिए भी ब्रॉडकास्ट अधिकार खरीदने होते हैं। आईसीसी इवेंट्स के राइट्स स्टार और जियो के पास हैं, इस वजह से आईसीसी के मैचों का प्रसारण वहां किया जाएगा, राइट्स बिकने के बाद ही तय हो गया था कि लाइव प्रसारण स्टार और जियो मिलकर करेंगे।

अन्य देशों के मैचों का क्या होगा?

स्टार और जियो सिर्फ भारत में ही सीधा प्रसारण करेंगे, अन्य देशों में लाइव टेलीकास्ट के लिए दूसरे चैनल होंगे। उन देशों के चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बांग्लादेश इस इवेंट से बाहर हो गया है लेकिन वहां भी वर्ल्ड कप के मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

एनएसडी के दिनों और इरफान खान को संजय मिश्रा ने किया याद, बोले- 'उन्हें देखना ही'

'वध 2' अब अपनी सिनेमाघर रिलीज के बेहद करीब है। ट्रेलर सामने आने के बाद से ही यह फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकारों की मौजूदगी ने इस स्पिरिचुअल सीक्वल को दर्शकों के बीच खास उत्सुकता का विषय बना दिया है।

एनएसडी में भावुक प्रमोशन इवेंट

फिल्म के प्रमोशन के तहत संजय मिश्रा, नीना गुप्ता और कुमुद मिश्रा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD), नई दिल्ली का दौरा किया। यह पल खास इसलिए भी रहा क्योंकि तीनों कलाकार इसी प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं। छात्रों, शिक्षकों और रंगमंच प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे यह आयोजन एक भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव में बदल गया।

संजय मिश्रा ने याद किए संघर्ष के दिन

एनएसडी में बातचीत के दौरान संजय मिश्रा ने अपने शुरूआती दिनों को याद किया और बताया कि किस तरह महान कलाकारों को करीब से देखने से उन्होंने अभिनय की असली समझ विकसित की। उन्होंने दिवंगत इरफान खान का ज़िक्र करते हुए कहा कि उन्हें देखकर यह समझ आता था कि अभिनय क्या होता है। उनके अनुसार, एनएसडी में सीख सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि सीनियर कलाकारों को ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ी शिक्षा थी।

इरफान खान से मिली प्रेरणा

संजय मिश्रा ने बताया कि इरफान खान, वीरेंद्र सक्सेना और अन्य वरिष्ठ कलाकारों को मंच पर देखते हुए उन्हें अभिनय की गहराई समझ में आई। उन्होंने कहा कि इरफान खान का अभिनय इतना सहज होता था कि कई बार लगता था कि वह अभिनय कर ही नहीं रहे, बल्कि उस किरदार को जी रहे हैं। उनकी ये बातें वहां मौजूद छात्रों के लिए बेहद प्रेरणादायक रहीं।

नई कहानी, नए किरदार

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित 'वध 2' में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म अपनी मूल कहानी की भावनात्मक और दार्शनिक गहराई को आगे बढ़ाती है, जो इसे सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक स्वतंत्र अनुभव बनाती है।

IFFI में मिला शानदार रिस्पॉन्स

फिल्म को 56वें IFFI 2025 में गाला प्रीमियर के रूप में दिखाया गया था, जहां इसे दर्शकों से जबरदस्त सराहना और तालियां मिलीं। इस रिस्पॉन्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता भारतीय सिनेमा के मजबूत स्तंभ हैं। 'लव फिल्म्स' के बैनर तले बनी 'वध 2' का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने किया है।

पाकिस्तान : रावलपिंडी जिला पुलिस ने भूत पर ठोका मुकदमा, जांच में जुटी टीमें, नाबालिग बच्चों से जुड़ा है मामला

पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले से एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक 11 साल के लड़के के लापता होने के बाद रविवार को 'जिन्न' यानी आत्मा या आम भाषा में कहें तो भूत के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। इस घटना की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने एआरवाई न्यूज के हवाले से दी है।

अचानक गायब हुआ बच्चा

यह घटना रावलपिंडी के छावनी शहर की है, जहां 21 जनवरी को एक 11 साल का लड़का अचानक अपने घर से लापता हो गया। परिवार ने बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे के अचानक गायब होने से परिवार में डर और चिंता का माहौल बन गया।

पिता ने पुलिस में दर्ज कराई ऋक्र

जब बच्चे का 10 दिनों तक कोई पता नहीं चला, तब उसके पिता ने तक्षशिला पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में पहली सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

जिन्न ने बेटे को बहकाकर भगाया- पिता

FIR में बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि जिन्न के नाम से जानी जाने वाली अलौकिक शक्तियों ने उनके बेटे को घर से भागने पर मजबूर किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये जिन्न पहले भी उनके बेटे को कई बार 'अपहरण' कर चुके हैं।

पहले लौट आता था बच्चा, इस बार नहीं लौटा

पिता ने बताया कि पिछली बार जब भी ऐसी घटनाएं हुई थीं, तब लड़का कुछ समय बाद खुद ही घर लौट आता था। लेकिन इस बार 10 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चा वापस नहीं आया। इसी वजह से पिता ने औपचारिक रूप से जिन्न के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया।

पाकिस्तान में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे दावे

अफ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की कानूनी व्यवस्था में इससे पहले भी इस तरह के अजीबोगरीब मामले दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले लाहौर में एक महिला ने अपनी शादीशुदा बेटी के लापता होने पर जिन्न के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जो बाद में अदालत तक पहुंचा।

लाहौर हाईकोर्ट ने SIT गठित करने के दिए थे आदेश

सितंबर में डॉन अखबार की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम के निर्देश पर लाहौर पुलिस ने एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाई थी। इस टीम को छह साल पुराने एक लापता महिला के मामले की जांच सौंपी गई थी।

जिन्न द्वारा अगवा किए जाने की आशंका में हुई जांच

उस मामले में यह माना जा रहा था कि महिला को एक जिन्न ने अगवा कर लिया था। जांच के लिए बनाई गई रक्ळ का नेतृत्व लाहौर जांच के डीआईजी जीशान रजा कर रहे थे।

महिला को ढूंढकर बरामद करने की जिम्मेदारी

DIG जीशान रजा को विशेष रूप से उस महिला का पता लगाने और उसे सुरक्षित बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह मामला पाकिस्तान में अंधविश्वास और कानूनी प्रक्रियाओं के टकराव का एक बड़ा उदाहरण माना गया था।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कारिडोर की डिजाइन तैयार करेगी आयसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

लखनऊ : (जीएनएस)। लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कारिडोर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने विस्तृत डिजाइन सलाहकार (डीडीसी) का चयन कर लिया है। आयसा इंडिया प्रा. लि. ईस्ट-वेस्ट कारिडोर भूमिगत मेट्रो स्टेशन का डिजाइन तैयार करने में मदद करेगी।

यूपीएमआरसी ने इस कारिडोर पर पहला टेंडर फाइनल कर दिया है। कुल 15.90 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाने वाली आयसा का चयन पांच वर्ष के लिए किया गया है। यूपीएमआरसी इसी अवधि के भीतर ही 11.165 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट कारिडोर का काम पूरा करेगा।

चारबाग से बसंतकुंज तक कारिडोर में 12 स्टेशन होंगे। बसंतकुज से ठाकुरगंज तक लगभग 4.286 किमी. का एलिवेटेड सेक्शन होगा। इसमें पांच स्टेशन होंगे। इसी तरह चारबाग - निवाजगंज के बीच 6.879 किमी. का भूमिगत सेक्शन होगा। इस सेक्शन पर ही घनी आबादी के बीच सात भूमिगत स्टेशन होंगे।

यूपीएमआरसी ने अगस्त 2025 में अपने डीडीसी अनुबंध के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं, जिसकी अवधि 60 महीने थी। इस दौरान तकनीकी बोलियां अक्टूबर में खोली गईं, जिनमें दो बोलीदाता आयेसा और सिस्ट्रा सामने आए। उनकी वित्तीय बोलियां 21 जनवरी को खोली गईं, जिनमें आयेसा को सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में 5801 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले कारिडोर के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। वहीं, रविवार को पेश हुए बजट में भी केंद्र सरकार के अंश के लिए 1450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

आयसा इंडिया मेट्रो, रेलवे, सुरंग, राजमार्ग और जलमार्ग सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने में विशेषज्ञता रखती है। इसकी सेवाओं में व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत डिजाइन से लेकर निर्माण पर्यवेक्षण, तकनीकी सहायता और व्यापक परियोजना प्रबंधन तक शामिल हैं। इसके साथ ही कामर्शियल उपयोग सहित यात्री सुविधाओं के लिए रिपोर्ट बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आयसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुख्य रूप से मेट्रो, रेलवे, टनल, हाईवे और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय नोएडा में है। आयसा ने दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी रेल प्रोजेक्ट पर काम किया है।

लखनऊ से गाजियाबाद तक बनेगा 4 लेन रेल ट्रैक:ट्रेनों की लेटलतीफी से मिलेगी राहत

लखनऊ रूट पर 450 किमी. में रोज चलती हैं 300 से ज्यादा ट्रेनें

(जीएनएस)।

लखनऊ से दिल्ली-एनसीआर के बीच रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ से गाजियाबाद तक रेलमार्ग को चार लेन करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस योजना के तहत हापुड़ और बरेली रूट पर अतिरिक्त रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे लखनऊ रूट पर ट्रेनों का दबाव कम होगा और लेटलतीफी में सुधार आएगा।

लखनऊ रूट पर 450 किलोमीटर में रोज चलती हैं 300 से ज्यादा ट्रेनें

लखनऊ से गाजियाबाद के बीच करीब 450 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर प्रतिदिन 300 से 350 ट्रेनें संचालित होती हैं। फिलहाल दो ही ट्रैक होने के कारण इस रूट पर ट्रेनों की भीड़ बनी रहती है। चार लेन ट्रैक बनने से लखनऊ रूट पर ट्रेनों की आवाजाही सुचारु हो सकेगी और संचालन अधिक सुरक्षित होगा।

लखनऊ से दिल्ली और पश्चिमी यूपी का कनेक्शन होगा मजबूत

इस परियोजना से लखनऊ का सीधा लाभ दिल्ली-एनसीआर, मेरठ, हापुड़ और बरेली से जुड़ाव के रूप में मिलेगा। रेल अधिकारियों के मुताबिक, नई लाइनों के बनने से लखनऊ से चलने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं मालगाड़ियों को अलग ट्रैक मिलने से यात्री ट्रेनों में देरी कम होगी।

लखनऊ रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी से मिलेगी राहत

अभी लखनऊ रूट पर ट्रेनों को अक्सर सिग्नल और क्रॉसिंग के कारण रोका जाता है, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। चार लेन ट्रैक बनने के बाद एक साथ अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा, जिससे लखनऊ से चलने और आने वाली ट्रेनों का समय बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।

लखनऊ से जुड़ी रेल परियोजना 2025-26 तक पूरी करने का लक्ष्य

रेलवे विभाग ने इस परियोजना के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम तेजी से चल रहा है। योजना है कि 2025-26 तक गाजियाबाद-लखनऊ चार लेन रेल ट्रैक परियोजना को पूरा कर लिया जाए, जिससे लखनऊ रेल नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी।

ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर घायल:सिधौली के पास लखनऊ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से गिरा, अस्पताल में भर्ती

(जीएनएस)।

सीतापुर के सिधौली के पास लखनऊ से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

यह घटना उस समय हुई जब युवक ट्रेन के गेट पर खड़ा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने 112 पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।

घायल युवक की पहचान आलोक (27 वर्ष) पुत्र तेजपाल, निवासी गेरुआ, थाना रामपुर कला के रूप में हुई है। आलोक ने बताया कि वह लखनऊ से पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ था और मोहल्ला पुर स्टेशन से बैठकर सिधौली की ओर आ रहा था।

सिधौली स्टेशन पहुंचने से पहले वह ट्रेन के गेट पर खड़ा हो गया था। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर ट्रेन से नीचे गिर गया।

लखनऊ में खुद की शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक को डंपर ने कुचला, भाई की हालत नाजुक

किसान पथ पर आनंदी वाटर पार्क के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया.

लखनऊ , (जीएनएस)। बीबीडी इलाके में शनिवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. युवक अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था. किसान पथ पर डंपर ने रौंद दिया. हादसे में उसका ममेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है.

13 फरवरी को थी शादी : गुडम्बा के श्रीकृष्ण पुरवा निवासी गोपी कुमार (23) की शादी 13 फरवरी को होनी थी. घर में 9 फरवरी को होने वाले तिलक समारोह की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो गया था. शनिवार शाम गोपी अपने मामा के लड़के गोविंद के साथ बाइक से शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था, लेकिन किसे पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा.

किसान पथ पर डंपर ने रौंदा : हादसा शाम करीब 7:30 बजे किसान पथ पर आनंदी वाटर पार्क के पास हुआ. गोपी अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गोपी की मौके पर ही जान चली गई. हादसे में घायल गोविंद को आनन-फानन में ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

डंपर चालक हिरासत में : इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया घटना की सूचना मिलते ही बीबीडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

चमकदार और आधुनिक होंगे रेलवे स्टेशन; बढ़ेगी सुरक्षा

यूपी: 20 हजार करोड़ से यूपी में ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार,

लखनऊ , (जीएनएस)। केंद्रीय बजट जारी होने के बाद उत्तर रेलवे के डीआरएम सुनील वर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में 4330 रूट किमी रेलखंड पर कवच सिस्टम सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा।

केंद्रीय बजट में यूपी में रेलवे के कायाकल्प के लिए 20012 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। इससे प्रदेश में ट्रेनों को रफ्तार देने, हाईस्पीड ट्रैक, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशनों, सेफ्टी आदि से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। दिल्ली में सोमवार को प्रेसवार्ता में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। इसका हजरतगंज स्थित उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम कार्यालयों में भी प्रसारण हुआ।

इसके बाद मंडल रेल प्रबंधक सुनील वर्मा एवं गौरव अग्रवाल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि गत वर्ष बजट में यूपी में रेलवे की गतिविधियों के लिए 19858 करोड़ रुपये दिए गए थे, जो इस बार बढ़ाकर 20012 करोड़ रुपये किए गए हैं। यह कांग्रेस की सरकारों में दिए गए बजट से कई गुना अधिक है। बजट में खास बात यह है

कि देशभर में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने हैं, जिसमें दो यूपी को मिले हैं।

दिल्ली से वाराणसी व वाराणसी से सिलिगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसकी डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी। हालांकि ट्रेनें किन रूटों से गुजरेंगी, इससे संबंधित सवालों के जवाब रेलमंत्री ने नहीं दिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली से वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर यूपी के कई शहरों को जोड़ेगा। यह यात्रा 3.50 घंटे में पूरी हो सकेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में 7746 करोड़ रुपये की लागत से 157 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम में विकास कराया जा रहा है। इसमें 22 स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है। लखनऊ के बादशाहनगर, डालीगंज, सिटी आदि स्टेशनों को विकसित कर दिया गया है।

कवच सिस्टम से सुरक्षा होगी पुख्ता

उत्तर रेलवे के डीआरएम सुनील वर्मा ने बताया कि प्रदेशभर में 4330 रूट किमी रेलखंड पर कवच सिस्टम सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। 71 रूट किलोमीटर सेक्शन में लग चुका। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 से अब तक 5500 किमी रेलखंड का निर्माण हो चुका है। जो स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर है।

34 वंदे भारत, 36 अमृत भारत ट्रेनें दौड़ रहीं

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपी में वर्ष 2014 से अब तक 7,176 किमी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। साथ ही 34 वंदे भारत और 36 अमृत भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। 1694 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा चुके हैं।

शब-ए-बरात की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन, शाम पांच बजे से अगली सुबह पांच बजे तक बदला रहेगा यातायात

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को शब-ए-बरात की वजह से ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। जानें, गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट अपनाएं:

शब-ए-बरात के मद्देनजर मंगलवार को पुराने लखनऊ व आसपास के इलाकों में यातायात परिवर्तित रहेगा। शाम पांच बजे से अगली सुबह 5 बजे तक यह परिवर्तन लागू रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को निकलवाएगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

- सीतापुर, मड़ियांव की ओर से आने वाले वाहन डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल की ओर नहीं जा सकेंगे। ये चौराहा नंबर आठ, निराला नगर, आईटी होकर जाएंगे।

- हरदोई रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहन (रोडवेज बसों को छोड़कर) दुबग्गा पेट्रोल पंप तिराहे से बालागंज, चौक की ओर नहीं आ सकेंगे। ये बुद्धेश्वर, आईआईएम सीतापुर रोड होकर जा सकेंगे।

विज्ञापन

- कैसरबाग बस अड्डे से सीतापुर की ओर जाने वाली रोडवेज बसें एवं भारी वाहन डालीगंज पुल से

शाहमीना, पक्कापुल की ओर नहीं जाएंगे। ये डालीगंज पुल चौराहे से दाहिने आईटी चौराहा, निराला नगर, पुरनिया होकर जा सकेंगे।

- कैसरबाग बस अड्डे से हरदोई रोड की ओर जाने वाली रोडवेज बसें शाहमीना से पक्कापुल की ओर नहीं जा सकेंगी। ये शाहमीना तिराहे से बाएं मेडिकल कॉलेज, मेडिकल क्रास (चरक), कोनेश्वर चौराहा होते हुए जाएंगी।

- कैसरबाग, हजरतगंज की ओर से आने वाले वाहन शाहमीना तिराहा से पक्का पुल की ओर नहीं जा सकेंगे। ये मेडिकल कॉलेज, चौक से कोनेश्वर या डालीगंज पुल चौराहे से दाएं आईटी चौराहा होकर जाएंगे।

- पक्का पुल खदरा साइड तिराहे से वाहन पक्कापुल चौक की ओर नहीं जाएंगे। ये नया पुल बंधा रोड, डालीगंज बाजार होकर जाएंगे।

- नीबू पार्क (रूमी गेट पुलिस चौकी) चौराहे से वाहन बड़ा इमामबाड़ा, पक्का पुल की ओर नहीं जा सकेंगे। ये मेडिकल कॉस, चौक व नए पुल से होकर जा सकेंगे।

- कोनेश्वर चौराहे से वाहन नींबू पार्क चौराहे (रूमी गेट) की ओर नहीं जा सकेंगे। ये चौक, बालागंज होकर जाएंगे।

- रकाबगंज पुल से वाहन नादान महल रोड (नक्खास) की ओर नहीं जा सकेंगे। ये मेडिकल कॉलेज, नाका होकर जा सकेंगे।

- राणा प्रताप चौराहे से आगे नया ओवर ब्रिज ढाल से ऐशबाग की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। ये चारबाग, नत्था, मवैया होकर जा सकेंगे।

- नाका हिंडोला चौराहे से बड़े वाहन, चार पहिया वाहनों को ऐशबाग पुल की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। ये रकाबगंज पुल, नत्था, मवैया होकर जा सकेंगे।

- दो पहिया वाहन मोतीनगर, राजेंद्र नगर चौराहे से आगे और ऐशबाग पुल के नीचे ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा सकेंगे। ये मोतीनगर, राजेंद्र नगर व ऐशबाग स्टेशन रोड, भूसामंडी होकर जा सकेंगे।

- हैदरगंज तिराहे (लाल माधव) से ऐशबाग ईदगाह, ऐशबाग पुल की तरफ दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त कोई भी चार पहिया अथवा भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। ये बुलाकी अड्डा, मिल एरिया होकर जाएंगे।

- स्टेशन रोड, कानपुर रोड से आने वाले भारी वाहनों को मवैया तिराहे से एवरेडी, मिल एरिया की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। ये चारबाग, आलमबाग होकर जाएंगे।

- आलमबाग चौराहे से भारी वाहन (लंगड़ा फाटक) बाबू जगजीवन राम अकादमी, एवरेडी, मिल एरिया की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये आलमबाग, बाराबिरवा होकर जाएंगे।

- शांतिनगर चौराहे से वाहन कुड़ियाघाट की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये बालागंज चौराहे से होकर जा सकेंगे।

लखनऊ में एमिटी उड़ान टैलेंट शो का आयोजन:बच्चों को मिला अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाने का मंच

(जीएनएस)।

लखनऊ में अमिटी इंटरनेशनल स्कूल, वृंदावन योजना कैंपस ने एक भव्य टैलेंट शो 'अमिटी उड़ान झ छोटे कदम, बड़े सपने' का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एमराल्ड मॉल, आशियाना में हुआ, जिसका उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

यह टैलेंट शो सभी के लिए खुला था, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और अन्य प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मॉल परिसर में बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और उत्सव का माहौल रहा।

बच्चों की मधुर आवाजों ने खूब तालियां बटोरीं

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न कला रूपों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें वॉटर कलर पेंटिंग, आर्ट और स्केचिंग, तथा मंडाला आर्ट जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिन्होंने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। बच्चों की कल्पनाशीलता और

धैर्य इन प्रस्तुतियों में साफ झलक रहा था।

इसके अतिरिक्त, वोकल सिंगिंग में बच्चों की मधुर आवाजों ने खूब तालियां बटोरीं, जबकि उनकी नृत्य प्रस्तुतियों में ऊर्जा और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'भारत ब्लिंग फैशन शो' रहा। इसमें बच्चों ने भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का एक शानदार संगम प्रस्तुत किया। पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक अंदाज ने दर्शकों का मन मोह लिया और हर प्रस्तुति पर लोगों ने जमकर सराहना की।

अमिटी उड़ान' बच्चों को आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर

इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रोली त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे मंच बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि 'अमिटी उड़ान' बच्चों को आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर देता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और रचनात्मक सोच को नई दिशा मिलती है। उन्होंने अभिभावकों और समाज की सहभागिता को बच्चों के मनोबल को मजबूत करने वाला बताया।

कार्यक्रम का समापन उत्साह और प्रेरणा के संदेश के साथ हुआ, जिसमें बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और अपने सपनों को उड़ान देने की खुशी साफ झलक रही थी।

जश्न रियल्टी ने लखनऊ में ₹3,200 करोड़ के निवेश की घोषणा की, राजधानी में कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की

यूपी का राजधानी लखनऊ में बड़े निवेश आ रहे हैं। इसी क्रम में जश्न रियल्टी भी निवेश करने जा रही है। लखनऊ में कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।

लखनऊः (जीएनएस)। राजधानी लखनऊ में जश्न रियल्टी बड़ा निवेश करने जा रही है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कंपनी के नेतृत्व ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना साझा की। प्रबंध निदेशक राहुल अग्रवाल ने बताया कि कंपनी आगामी तीन वर्षों में रियल एस्टेट विकास क्षेत्र में लगभग ₹3,200 करोड़ का निवेश

करने जा रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल अग्रवाल ने कहा कि जश्न रियल्टी की विस्तार रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगी, जो लखनऊ जैसे टियर-वन शहरों में बढ़ती मांग के अनुरूप हैं। उन्होंने शहर के तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते निवेशकों के विश्वास को इस बड़े निवेश निर्णय के प्रमुख कारण बताया। राहुल अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की तेज और समयबद्ध डिलीवरी कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि समय से पहले और तेज डिलीवरी अब केवल एक अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। जश्न रियल्टी में हम अपनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, निष्पादन टीमों को मजबूत बना रहे हैं और उन्नत निर्माण योजना को अपनाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स तय समय से पहले ग्राहकों तक पहुंचे।

कंपनी ने यह भी बताया कि आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में ग्राहक-केंद्रित डिजाइन, नियामकीय अनुपालन और पारदर्शी निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जश्न रियल्टी का लक्ष्य निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और सतत विकास मानकों से समझौता किए बिना डिलीवरी टाइमलाइन में नए मानक स्थापित करना है।

अयोध्या-लखनऊ कॉरिडोर बनेगा आस्था और पर्यटन का सुपरहाइवे, नैमिषारण्य से वृंदावन तक बदलेगा सफर का अनुभव

(जीएनएस)।

लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने वाला करीब 125 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अब सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और रोजगार का नया द्वार बनने जा रहा है। केंद्रीय बजट में अतिरिक्त धनराशि मिलने के बाद इस परियोजना को पर्यटन पैकेज से जोड़ा गया है। इसका सीधा लाभ बाराबंकी जिले को मिलेगा, जहां धार्मिक और इको-टूरिज्म के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

NH-27 पर इको-टूरिज्म और धार्मिक स्थलों का विकास

राष्ट्रीय राजमार्ग ठल-27 को इको-टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर हरियाली, पर्यटन सुविधाएं और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, बल्कि एक सुरम्य और यादगार यात्रा अनुभव देना है। आने वाले समय में यह मार्ग देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

नैमिषारण्य से वृंदावन तक सुरक्षित कनेक्टिविटी

इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लखनऊ से किसान पथ के जरिए नैमिषारण्य चक्रतीर्थ को जोड़ेगा और आगे आगरा एक्सप्रेस वे के माध्यम से मथुरा-वृंदावन तक सीधी, सुरक्षित कनेक्टिविटी देगा। यानी श्रद्धालु अब अयोध्या, नैमिषारण्य और वृंदावन जैसे प्रमुख तीर्थों की यात्रा कम समय में, बिना जाम और जोखिम के कर सकेंगे।

बाराबंकी के तीर्थ बनेंगे पर्यटन के नए केंद्र

कॉरिडोर के रास्ते बाराबंकी के कई प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी पर्यटन मानचित्र पर उभरेंगे। रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेवा तीर्थ में पृथ्वी पर उपलब्ध 52 दुर्लभ और अनोखे शिवलिंगों के दर्शन संभव होंगे। सिरौलीगौसपुर क्षेत्र के किंतूर में कुंतेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता है कि यहां शिवलिंग प्रतिदिन स्वतः पूजित अवस्था में मिलते हैं।

पारिजात वृक्ष से कोटवाधाम तक, आस्था का पूरा सर्किट

बरौलिया का देव वृक्ष पारिजात, कोटवाधाम तीर्थ जहां समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब की तपोस्थली है, सतरिख का मंजीठा धाम और हैदरगढ़ का औसानेश्वर महादेव मंदिर—ये सभी स्थल अब बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण श्रद्धालुओं के लिए आसानी से सुलभ होंगे। साथ ही भगहर झील में विदेशी पक्षी सारस का प्रवास इको-टूरिज्म को नया आयाम देगा।

चार फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति

यातायात दबाव को देखते हुए एनएचएआई ने इस कॉरिडोर पर चार प्रमुख फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है। सफेदाबाद, दादरा, सफदरगंज और दिलोना मोड़ पर बनने वाले फ्लाईओवर से रोजाना करीब 22 हजार वाहनों की आवाजाही सुचारु होगी। कार, बस और भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।

पर्यटन के साथ रोजगार की नई राह

एनएचएआई के अनुसार इस परियोजना का लक्ष्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। होटल, ढाबे, गाइड सेवा, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या-लखनऊ कॉरिडोर आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन विकास की रीढ़ साबित हो सकता है।

आशा कर्मियों की हड़ताल जारी, नौ को जाएंगी लखनऊ

बदायूं। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर 15 दिसंबर से जारी आशा कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। आशाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। लगातार लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस पहल न होने से आशा कर्मियों में रोष व्याप्त है। वे प्रदर्शन करने नौ फरवरी को लखनऊ जाएंगी।

यूनियन की जिलाध्यक्ष जौली वैश्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार द्वारा कल पेश किए गए बजट में आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी कर्मियों को कुछ देना तो दूर, उनका नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा गया। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार भी पिछले 49 दिनों से संघर्षरत आशा कर्मियों से बात करने तक को तैयार नहीं है। धरना स्थल पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, जनपद शाखा बदायूं के शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार पहुंचकर आशा कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दिया। धरने में यूनियन की सचिव मुनीषा ने भी विचार रखे।

लखनऊ में भाजपा विधायक के भतीजे ने की आत्महत्या, पंखे से लटकता मिला शव, पार्टनरों पर धोखे का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक शिवम के बिजनेस पार्टनरों ने उसके पैसे हड़प लिए थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान चल रहा था और तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया.

राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के भतीजे शिवम त्रिपाठी ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली. शिवम का शव फ्लैट के कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये घटना लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में स्थित मैनहैटन टॉवर की है. शिवम यहां टॉवर अ2 के फ्लैट नंबर 407 में रहता था. परिजनों का कहना है कि शिवम प्रॉपर्टी का किया करता था और वो पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी के काम लगे उनके पार्टनरों के साथ पैसों को लेकर परेशान था.

फ्लैट में पंखे से लटकता मिला शव

रविवार की शाम को जब काफी देर तक उसके घर का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब किसी तरह घर का दरवाजा तोड़ा तो कमरे का नजारा देखकर होश उड़ गए. शिवम का शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला.

परिजनों ने सहयोगियों पर लगाए गंभीर आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बिजनेस पार्टनरों ने उसके पैसे हड़प लिए थे, वो काफी समय से उनसे पैसे माँग रहा था लेकिन, वो ना तो उसका ठीक से जवाब दे रहे थे और नहीं उसके पैसे वापस कर रहे थे. सहयोगियों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वो काफी परेशान रहने लगा था और तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया.

शिवम त्रिपाठी बीजेपी विधायक विनय कुमार त्रिवेदी के भतीजे हैं और यूपी के बलरामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. मृतक के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लिया गया है.

लखनऊ और गोरखपुर के बीच होगी खिताबी जंग

(जीएनएस)।

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित गौतम बुद्ध ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-4 का दूसरा सेमीफाइनल सोमवार को रोमांच से भरपूर रहा। दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को पांच विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब मंगलवार को खिताबी मुकाबले में लखनऊ का सामना गोरखपुर से होगा। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए लखनऊ के आशुतोष चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

मैच में लखनऊ के कप्तान यशवर्धन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने आक्रामक शुरूआत की और निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 199 रन का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की ओर से प्रतीक रमन ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए नाबाद 87 रन की बेहतरीन पारी खेली। विकास राय ने 47 रन की उपयोगी पारी खेली। भास्कर भारद्वाज ने 28 और सक्षम राय ने 17 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

लखनऊ की गेंदबाजी में तुषार सबसे सफल रहे, जिन्होंने 2 विकेट झटके जबकि आशुतोष, अमित और आदित्य को एक-एक विकेट मिला।

200 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने दबाव के बावजूद संयम और आक्रामक के साथ बेहतरीन संतुलन खेल दिखाया।

शुरूआती विकेट गिरने के बाद भी बल्लेबाजों ने रन गति बनाए रखी। समय ने 39 रन की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। इसके बाद संदीप गुप्ता और आशुतोष चौधरी ने 32-32 रन बनाकर लक्ष्य को करीब पहुंचाया। अंत में राजकुमार ने नाबाद 40 रन की अहम पारी खेलते हुए टीम को पांच विकेट शेष रहते जीत दिला दी। दिल्ली की ओर से गेंदबाजी में भास्कर ने 2 विकेट हासिल किए जबकि आनंद, सक्षम और सचिन को एक-एक विकेट मिला।

मैच के मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम जायसवाल रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की।

जेल से भागे बंदियों की तलाश में लखनऊ रूट की ट्रेनों पर नजर

अयोध्या , (जीएनएस)। जिला जेल से भागे बंदियों की तलाश में लखनऊ की रूट की ट्रेनों पर पुलिस की नजर है। इसके लिए बुधवार की रात गईं लगभग छह ट्रेनों के रूट की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अब तक की जांच में पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।

सुल्तानपुर के करौंदीकला, अमरे मऊ निवासी शेर अली और अमेठी के मुसाफिरखाना निवासी गोलू अग्रहरि जिला जेल की विशेष सुरक्षा बैरक से भाग निकले थे। कारापाल जितेंद्र कुमार यादव की तहरीर पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन की जा रही है। पुलिस ने जेल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में बंदियों के पोस्टमार्टम हाउस के सामने स्थित बाउंड्री पार करके ट्रेन पकड़ने की प्रबल संभावना है।

इसी मकसद से बुधवार की रात गुजरीं ट्रेनों की पड़ताल की गई। सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार की भोर में 03:30 बजे छपरा से फरुखाबाद, 03:10 बजे वाराणसी से बरेली, सुबह 06:35 बजे कोलकाता से जम्मू, 05:45 बजे अयोध्या से लखनऊ, 05:25 बजे आनंद बिहार से रक्सौल ट्रेन रवाना हुई हैं। इन्हीं ट्रेनों से बंदियों के भागने की आशंका जताई जा रही है। इनके संभावित रूटों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि हर एंगल पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

हाईवे पर खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे

दोनों बंदी जेल से भागने के बाद रोडवेज की तरफ जाते नहीं दिखे हैं। इसलिए उनके हाईवे से भी भागने की आशंका है। इस लिहाज से पुलिस की अलग-अलग टीमें हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर रही हैं। माना जा रहा है कि माल वाहनों में लिफ्ट मांगकर भी वह भाग सकते हैं। यहां से भी अब तक कोई इनपुट नहीं मिल सका है।

यूपी बार काउंसिल यूपी चुनाव प्रयागराज में संपन्न:लखनऊ में चुनाव रद्द, हाईपावर कमेटी तय करेगी नई तारीख; 23,414 मत पड़े

प्रयागराज, (जीएनएस)। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सामान्य निर्वाचन का मतदान प्रयागराज स्थित कार्यालय में 30 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुआ। चुनाव में कुल 333 प्रत्याशी मैदान में है। यह चुनाव निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार त्रिपाठी, पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट इलाहाबाद तथा पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह, पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट इलाहाबाद के प्रत्यक्ष निर्देशन में कराया गया।

चार दिवसीय मतदान में प्रयागराज के 33 हजार वोटरों में से कुल 23,414 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के पहले दिन 30 जनवरी को 6,644 वोट पड़े। दूसरे दिन 31 जनवरी को 5,630 मतदाताओं ने मतदान किया। तीसरे दिन 1 फरवरी को 3,649 वोट डाले गए, जबकि अंतिम और चौथे दिन 2 फरवरी को सबसे अधिक 7,491 मत पड़े। अंतिम दिन भारी भीड़ के बीच मतदान देर शाम तक जारी रहा।

चुनाव को सफल बनाने में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अहम भूमिका रही। हाईकोर्ट इलाहाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री विद्याकान्त, जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट एवं अपर जनपद न्यायाधीश श्री रविकान्त द्वितीय सहित कई अधिकारी और कर्मचारी पूरे समय व्यवस्था में जुटे रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसीपी सिविल लाइन्स श्री विद्युत गोयल और एसीपी काइम श्री अरुण कुमार त्रिपाठी ने संभाली। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती से मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।

इस बीच जनपद लखनऊ में हुए मतदान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए हाईपावर इलेक्शन कमेटी के निर्देश पर लखनऊ का चुनाव निरस्त कर दिया गया है। अब हाईपावर कमेटी की बैठक के बाद लखनऊ में पुनः मतदान की नई तिथि तय की जाएगी। इसकी आधिकारिक सूचना जल्द जारी की जाएगी।

बार काउंसिल प्रशासन ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी संस्थाओं का आभार जताते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना प्राथमिक उद्देश्य था, जिसमें सभी की सहभागिता से सफलता मिली।

केन्द्रीय बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटन

उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

रतलाम 02 फरवरी। माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियों कान्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक बल दिया गया है जिससे रेलवे पर उच्च-गति कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2026झ27 में भारतीय रेल के लिए 2,93,030 करोड़ रूपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई गई है। यह भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आवंटन है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 120 हजार करोड़ रूपए का आंवटन किया गया है।

माननीय रेलमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के निरंतर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश राज्य में रेलवे के विस्तार, सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 के बजट में 15,188 करोड़ रूपए आवंटन किया गया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। राज्य में 1,18,379 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को रुपए 3,163 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1283 फ्लाईओवर और रोड अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। माननीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात पर जोर दिया।

संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेलमार्गों पर स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य तीव्र गति से किये जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 4591 रूट किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेन्टर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते है।

यात्री सुविधाओं के विषय में माननीय रेलमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को कवर करते हुए 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एवं 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के लिए यह रेल बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।

माननीय रेलमंत्री जी ने बताया कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। 2,052 किमी लंबा यह कॉरिडोर मौजूदा पश्चिमी समर्पित मालवाहक कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक माल की बिना किसी रुकावट के आवाजाही हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यह पूर्वझपश्चिम कॉरिडोर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापार प्रवाह को सुदृढ़ करेगा, मौजूदा रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी कहा कि उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेला को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे द्वारा तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मेला अवधि के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी तथा रेल संचालन एवं यात्री सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट 2026झ27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे ह्यविकसित भारतह्ल के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही माननीय रेलमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय बजट 2026झ27 में गुजरात राज्य को 17,366 करोड़ रुपये तथा राजस्थान राज्य को 10,288 करोड़ रुपये का रेल बजट आवंटन किया गया है। चूँकि पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल गुजरात एवं राजस्थान दोनों राज्यों को सीधे जोड़ता है, अतः इन दोनों राज्यों में रेल अवसंरचना, सेफ्टी एवं यात्री सुविधाओं पर होने वाले विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ रतलाम मंडल को भी मिलेगा। इससे रतलाम मंडल में रेल परियोजनाओं, परिचालन क्षमता तथा यात्री सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

केन्द्रीय बजट 2026झ27 में घोषित पहलों के साथ, भारतीय रेलवे ह्यविकसित भारतह्ल के विजन के अनुरूप तेज कनेक्टिविटी, कुशल लॉजिस्टिक्स और सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। - जनसंपर्क विभाग

पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

बीएसआईपी लखनऊ में रॉक मैग्नेटिज्म कार्यशाला शुरू:भूविज्ञान में आधुनिक तकनीकों पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला

लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी) में 'रॉक मैग्नेटिज्म इन अर्थ साइंसेज (फ्टएर-2026)' विषय पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू हो गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भूविज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान से जुड़े छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों को रॉक मैग्नेटिज्म की आधुनिक तकनीकों तथा उनके व्यावहारिक उपयोगों से परिचित कराना है।

रॉक मैग्नेटिज्म चट्टानों और मिट्टी में मौजूद चुंबकीय गुणों का अध्ययन है। यह पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय बदलावों को समझने में सहायक है। इस क्षेत्र में हो रहे तीव्र तकनीकी विकास को देखते हुए, कार्यशाला में प्रतिभागियों को नवीन ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

संस्थान की आधुनिक प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी दी

कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में संयोजक डॉ. मोहम्मद आरिफ, वैज्ञानिक-डी ने बीएसआईपी के गौरवशाली इतिहास और संस्थान की आधुनिक प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रॉक मैग्नेटिज्म का उपयोग पुराचुंबकत्व, भूस्तरीय दिनांकन, प्लेट विवर्तनिकी और पुराजलवायु अध्ययनों में व्यापक रूप से किया जाता है।

सह-संयोजक डॉ. बिनिता फर्तियाल, वैज्ञानिक-एफ ने बताया कि बीएसआईपी की पुराचुंबकत्व प्रयोगशाला अब एक प्रमुख राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 'एप्लीकेशन एंड एडवांस इन पैलेयो रॉक एंड एनवायरनमेंट मैग्नेटिज्म' विषय पर इस प्रकार की क्षमता निर्माण कार्यशाला पहली बार आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्र से नमूना संग्रह, प्रयोगशाला तैयारी और आधुनिक विश्लेषण तकनीकों का प्रशिक्षण शामिल हैं।

बुनियादी समझ विकसित करने का बेहतर अवसर हैं

बीएसआईपी के निदेशक प्रो. एम.जी.ठक्कर ने कहा कि यह कार्यशाला छात्रों और युवा शोधकताओं के लिए रॉक मैग्नेटिज्म और पुराचुंबकत्व की बुनियादी समझ विकसित करने का एक बेहतर अवसर है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग पक्षी दिशा-निर्धारण में करते हैं, जिसे मैग्नेटोरिसेप्शन कहा जाता है।

मुख्य अतिथि प्रो. अशोक सहनी, एमेरिटस प्रोफेसर, पंजाब विश्वविद्यालय ने अपने शोध अनुभव साझा करते हुए बताया कि पुराचुंबकीय अध्ययनों ने दक्कन इंटरट्रेपियन शैलक्रमों की आयु निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मानित अतिथि प्रो. टी. राधाकृष्णा ने इस क्षेत्र में और अधिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।